REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2024

आयुष्मान भारत योजना (AYUSHMAN BHARAT SCHEME)

डॉ ओमप्रकाश मेहरड़ा
एसोसिएट प्रोफेसर, लोकप्रशासन एवं राजनीतिविज्ञानं विभाग, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय,
पीलीबंगा हनुमानगढ़ (राजस्थान)

ABSTRACT:

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना', आयुष्मान भारत 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिंदाबाद भारत';) भारत सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। मोटे तौर पर, देश के निचले 50% लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का उपयोग करने वाले लोग पारिवारिक डॉक्टर से अपनी प्राथमिक देखभाल सेवाओं का उपयोग करते हैं और जब किसी को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, तो पीएम-जेएवाई विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के लिए मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले लोगों के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है।

आयुष्मान भारत योजना
प्रोजेक्ट का प्रकार-स्वास्थ्य बीमा
मंत्रालय-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
शुरू-23 सितंबर 2018 ; 5
बजट-₹ 8,088 करोड़ (US$1.0 बिलियन) (2021–22) [1]
सक्रिय वेबसाइट-www .pmjay .gov .in
बिदिपेठ, नागपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

यह कार्यक्रम भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है और साधन-परीक्षित है । इसे सितंबर 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था । उस मंत्रालय ने बाद में कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। 50 करोड़ (500 मिलियन) लोगों को सेवाएं प्रदान करके यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य

सेवा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक साधन-परीक्षित कार्यक्रम है, यह देखते हुए कि इसके उपयोगकर्ता भारत में निम्न आय के रूप में वर्गीकृत लोग हैं ।

ईतिहास

2017 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के एक भारतीय संस्करण ने भारत के हर राज्य के लिए 1990 से 2016 तक प्रमुख बीमारियों और जोखिम कारकों की रिपोर्ट दी। इस अध्ययन ने सरकारी स्वास्थ्य नीति में बहुत रुचि पैदा की क्योंकि इसने प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान की जिनका सरकार समाधान कर सकती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली से वंचित रह जाता है, जो देखभाल के लिए मरीजों की जेब से किए जाने वाले भुगतान पर निर्भर रहता है। ये भुगतान बहुत से रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। 2018 में भारत सरकार ने बताया कि हर साल छह करोड़ से अधिक भारतीयों को जेब से इलाज पर होने वाले खर्च के कारण गरीबी में धकेल दिया जाता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बावजूद , अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत सरकार ने पहली बार फरवरी 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना के रूप में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की । केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने मार्च में इसे मंजूरी दे दी। अपने 2018 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत में उस वर्ष के अंत में 25 सितंबर को एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाएगा ।

PM-JAY टिकट

जून 2018 में "पैनलमेंट प्रक्रिया" के माध्यम से अस्पतालों के लिए आवेदन खोले गए। [उद्धरण वांछित] जुलाई 2018 में, आयुष्मान भारत योजना ने सिफारिश की कि लोग आधार के माध्यम से लाभ प्राप्त करें , लेकिन यह भी कहा कि लोगों के लिए उस पहचान पत्र के बिना लाभ प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। [उद्धरण वांछित] एबी पीएम-जेएवाई को पहली बार 23 सितंबर 2018 को रांची , झारखंड में लॉन्च किया गया था । 26 दिसंबर 2020 तक इस योजना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक बढ़ा दिया गया था। कार्यक्रम को "महत्वाकांक्षी" कहा गया है।

विशेषताएँ

बिहार के महुआ सामुदायिक विकास खंड में आयुष्मान भारत योजना के एक भाग के रूप में एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किया गया ।

PM-JAY की विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ भारतीयों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना; सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख (2023 में ₹ 5.6 लाख या यूएस $7,000 के बराबर) का कवर प्रदान करना ; अस्पताल या डॉक्टर के कार्यालय के माध्यम से कैशलेस भुगतान और कागज रहित रिकॉर्डकीपिंग की पेशकश; लाभ के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के मानदंडों का उपयोग करना ; परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं; पिछली सभी चिकित्सीय स्थितियाँ योजना के अंतर्गत कवर की गई हैं; इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के 15 दिन शामिल हैं, जिसमें नैदानिक देखभाल और दवाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है यह योजना पोर्टेबल है और लाभार्थी अपने राज्य के बाहर और देश में कहीं भी किसी भी पीएम-जेएवाई पैनल वाले अस्पताल में चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है; निःशुल्क कोविड-19 परीक्षण तक पहुंच प्रदान करना ।

भारत में, सार्वजनिक प्रणाली में आवश्यक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, बीमा-आधारित प्रणाली की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया गया है। निजी क्षेत्र की तुलना में भारत के सार्वजनिक

स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार कम फंडिंग और 1990 के दशक के अंत में भारत सरकार द्वारा निजी स्वास्थ्य बीमा के लिए बाजार के उदारीकरण के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य असमानताएं बढ़ गईं, क्योंकि निजी स्वास्थ्य बीमा केवल उच्च वर्ग के लिए ही किफायती है। समृद्ध समुदाय. 2000 के दशक के मध्य में, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा एक नए प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण के रूप में उभरा, जिससे व्यक्तियों को अपनी जेब से होने वाले विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय को रोकने में मदद मिली। इस मॉडल के माध्यम से, राज्य निजी बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करेगा जो पात्र व्यक्तियों को पीएमजेएवाई योजना में शामिल होने वाले किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्थान में मुफ्त इलाज प्राप्त करने की अनुमति देगा। भारत सरकार ने माना कि अपनी जेब से व्यक्तिगत खर्च लोगों को गरीबी में धकेल रहा है और सरकारी अस्पतालों में इलाज लोगों को विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय से नहीं बचा सकता है। [22] सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा का विकल्प गरीब व्यक्तियों को अतिरिक्त खर्चों के बिना निजी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी

भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना में भाग लेने के बारे में अपनी पसंद बनाते हैं। [उद्धरण वांछित] फरवरी 2018 में, जब कार्यक्रम की घोषणा की गई तो 20 राज्यों ने इसमें शामिल होने के लिए प्रतिबद्धता जताई।[उद्धरण वांछित] सितंबर 2018 में, लॉन्च के तुरंत बाद कुछ राज्यों और क्षेत्रों ने कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने शुरू में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के राज्य स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम थे। वे कार्यक्रम, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और तमिलनाडु के लिए कार्यक्रम, पहले से ही अच्छी तरह से काम कर रहे थे। बाद में ये दोनों राज्य विशेष अपवादों के साथ आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गए और इसे अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का हिस्सा बना लिया। इसी तरह, केरल , अपने स्वयं के स्वास्थ्य कार्यक्रम के बावजूद, नवंबर 2019 से आयुष्मान भारत योजना का उपयोग शुरू करने के लिए सहमत हुआ। पश्चिम बंगाल शुरू में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, लेकिन फिर अपना स्वयं का क्षेत्रीय स्थापित करने के पक्ष में बाहर हो गया। स्वास्थ्य कार्यक्रम. तेलंगाना ने भी ऐसा ही किया। जनवरी 2020 तक, ओडिशा इस योजना में शामिल नहीं हुआ था। मार्च 2020 में, दिल्ली ने घोषणा की कि वह इस कार्यक्रम में शामिल होगी।

स्थानीय लोगों की भागीदारी

मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात में कहा था कि आयुष्मान भारत योजना से हाल ही में एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है. मई 2020 तक, इस योजना ने ₹13,412 करोड़ मूल्य के 1 करोड़ से अधिक उपचार प्रदान किए थे । देश भर में सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या 24,432 है। आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम ने नवंबर 2019 में कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम के साथ एक विशेष सहयोग की घोषणा की । जून 2020 से, कार्यक्रम ने 15 अस्पतालों में 120,000 श्रमिकों को उस बीमा के साथ कवर करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम में प्रवेश किया था।

चुनौतियां

जब आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई तो सवाल थे कि इसकी योजनाओं को नीति आयोग जैसी अन्य मौजूदा स्वास्थ्य विकास सिफारिशों के साथ कैसे समेटा जाए । राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना को लागू करने की एक बड़ी चुनौती आधुनिक राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए विकास की आवश्यकता वाले बुनियादी ढांचे से शुरू करना होगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना चाहती है, भारत में अभी भी कुछ बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियाँ हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम डॉक्टर, संक्रामक रोग के अधिक मामले और स्वास्थ्य देखभाल में तुलनात्मक रूप से कम केंद्र सरकार का निवेश वाला राष्ट्रीय बजट शामिल है। कुछ समस्याएँ स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर हैं जैसे शहरी विकास या परिवहन। जबकि कई सरकारी अस्पताल इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं,

कई निजी कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं जुड़े हैं। निजी अस्पतालों की रिपोर्ट है कि वे सरकारी सब्सिडी के साथ भी, सरकारी कम कीमत पर अपनी विशेष सेवाएँ देने में असमर्थ होंगे।

फर्जी मेडिकल बिल जमा कर निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत योजना का दुरुपयोग किया गया है। योजना के तहत उन लोगों की सर्जरी करने का दावा किया गया है, जिन्हें काफी पहले छुट्टी मिल चुकी है और डायलिसिस को उन अस्पतालों में दिखाया गया है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है। अकेले उत्तराखंड राज्य में कम से कम 697 फर्जी मामले हैं , जहां योजना के तहत धोखाधड़ी के लिए अस्पतालों पर ₹ 1 करोड़ (2023 में ₹ 1.1 करोड़ या यूएस $140,000 के बराबर) का जुर्माना लगाया गया है। पीएम-जेएवाई के तहत उच्च-मूल्य के दावों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि अपेक्षाकृत कम संख्या में जिलों और अस्पतालों में इनकी संख्या अधिक है, और कुछ महिला विरोधी पूर्वाग्रह का संकेत देते हैं, जिसमें पुरुष रोगियों को अधिक कवरेज मिलता है। बेईमानी पर अंकुश लगाने के सभी प्रयासों के बावजूद, सिस्टम के गेमिं ग से मुनाफाखोरी करने वाली बेईमान निजी संस्थाओं का जोखिमPM-JAY में स्पष्ट रूप से मौजूद है।

संदर्भ

1. "बजट 2020: हेल्थकेयर को 69,000 करोड़ रुपये मिले; आयुष्मान भारत के लिए 6,400 करोड़ रुपये - ईटी हेल्थवर्ल्ड" ।
2. "आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण (राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण) योजना - आयुष्मान भारत" । Infnd . 17 जून 2015 । 28 नवंबर 2018 को लिया गया ।
3. "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के बारे में" । pmjay.gov.in . 2 मार्च 2020 को पुनःप्राप्त .
4. "आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा बनने की राह पर अरुण जेटली" । द इकोनॉमिक टाइम्स । पीटीआई. 6 मार्च 2019. 20 फरवरी 2021 को मूल से संग्रहीत ।15 फरवरी 2021 को लिया गया ।
5. डंडोना, ललित; डंडोना, राखी; कुमार, जी अनिल; शुक्ला, डीके; और अन्य। (दिसंबर 2017)। "एक राष्ट्र के भीतर राष्ट्र: भारत के राज्यों में महामारी विज्ञान संक्रमण में विविधताएं, 1990-2016 रोग अध्ययन के वैश्विक बोझ में" । नश्तर । 390 (10111): 2437-2460। डीओआई : 10.1016/एस0140-6736(17)32804-0 । पीएमसी 5720596 । पीएमआईडी 29150201 - एनसीबीआई के माध्यम से।
6. भार्गव, बलराम; पॉल, विनोद के (सितंबर 2018)। "आयुष्मान भारत की पूर्व संध्या पर भारत में एनसीडी नियंत्रण प्रयासों की जानकारी देना" । नश्तर । 399 (10331): ई17-ई19। डीओआई : 10.1016/एस0140-6736(18)32172-एक्स । पीएमआईडी 30219331 । S2CID 52189318 ।
7. एंजेल, ब्लेक जे.; प्रिंजा, शंकर; गुप्त, अनादि; झा, विवेकानन्द; जनवरी, स्टीफ़न (7 मार्च 2019)। "9:-आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग: प्रबंधन और शासन की चुनौतियों पर काबू पाना" । पीएलओएस दवा । 16 (3): ई1002759। doi : 10.1371/journal.pmed.1002759 । आईएसएसएन 1549-1676 . पीएमसी 6405049 . पीएमआईडी 30845199 ।
8. "चिकित्सा व्यय सालाना 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी की ओर धकेलता है: शीर्ष अधिकारी" । एनडीटीवी । प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. 17 नवंबर 2018. 17 नवंबर 2018 को मूल से संग्रहीत ।15 फरवरी 2021 को लिया गया ।
9. मुखर्जी, रीमा; अरोड़ा, मनीषा (2018)। "भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना: एक पूर्वावलोकन" । डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ का मेडिकल जर्नल । 11 (5): 385. दोई : 10.4103/mjdrdypu.mjdrdypu_109_18 । एस2सीआईडी 169815602 ।
10. "पीएम मोदी ने रांची में 12:-PMJAY-आयुष्मान भारत लॉन्च किया" । एएनआईन्यूज । 23 सितंबर 2018.
11. "पीएम मोदी 26 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे" । हिंदुस्तान टाइम्स । 24 दिसंबर 2020 । 26 दिसंबर 2020 को लिया गया ।

12. सिंह, पूनम खेत्रपाल (1 अक्टूबर 2018)। "आयुष्मान भारत: सुधारों का एक महत्वाकांक्षी सेट जिससे भारत के लाखों गरीबों और कमजोर लोगों को लाभ होना चाहिए" । विश्व स्वास्थ्य संगठन। 22 फरवरी 2020 को मूल से संग्रहीत । 15 फरवरी 2021 को लिया गया ।
13. ज़ोडपे, एस; फारूकी, एचएच (अप्रैल 2018)। "भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: हासिल की गई प्रगति और आगे का रास्ता" । इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च । 147 (4): 327-329. doi : 10.4103/ijmr.IJMR_616_18 । पीएमसी 6057252 । पीएमआईडी 29998865 ।
14. हमारा ब्यूरो (23 सितंबर 2018)। "पीएम ने आयुष्मान भारत का अनावरण किया; 50 करोड़ को मिलेगा ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर" । व्यवसाय लाइन ।
15. शर्मा, योगिमा सेठ (13 सितंबर 2019)। "श्रम मंत्रालय एबी-पीएमजेएवाई के तहत कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा" । द इकोनॉमिक टाइम्स ।
16. "एनएचए ने राज्यों को पात्र पीएमजेएवाई लाभार्थियों की पहचान करने की सलाह देते हुए परिपत्र जारी किया" । द इकोनॉमिक टाइम्स । 6 अक्टूबर 2018.
17. शर्मा, नीतू चंद्रा (10 जून 2019)। "मोदीकेयर के तहत अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए सरकार SECC 2011 से आगे की सोच रही है" । लाइवमिंट । एचटी मीडिया ।
18. शर्मा, नीतू चंद्रा (26 सितंबर 2019)। "आयुष्मान भारत के तहत 40,000 से अधिक लोगों ने पोर्टेबल उपचार का लाभ उठाया" । लाइवमिंट । एचटी मीडिया ।
19. कुमार, राजीव (27 मई 2020)। "पीएमजेएवाई के तहत मुफ्त सीओवीआईडी -19 परीक्षण: एनएचए आईसीएमआर अनुमोदित प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करेगा' । द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ।
20. कौल, रिदम (20 मई 2020)। "आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,000 का इलाज चल रहा है, 3,000 लोगों का मुफ्त में कोविड-19 परीक्षण किया गया" । हिंदुस्तान टाइम्स ।
21. हुडा, शैलेन्द्र कुमार (20 जून 2020)। "आयुष्मान भारत को डिकोड करना"। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक । 25 .
22. एक्स, स्टीफन (28 मई 2021)। " भारत में "मांग पक्ष" स्वास्थ्य बीमा: अस्पष्टता की कीमत" । मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी । 40 (5): 404–416। doi : 10.1080/01459740.2021.1929208 । ISSN 0145-9740 ।
23. "5 राज्यों ने आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का विकल्प चुना: इसका कारण जानें" । मनीकंट्रोल । 24 सितंबर 2018. 24 सितंबर 2018 को मूल से संग्रहीत । 15 फरवरी 2021 को लिया गया ।
24. "आयुष्मान भारत योजना और चिकित्सा उपकरण उद्योग पर इसका प्रभाव" । एक्सप्रेस हेल्थकेयर । 9 अक्टूबर 2020 । 15 फरवरी 2021 को लिया गया ।
25. पोरेचा, मैत्री (24 सितंबर 2019)। "एक साल बाद, आयुष्मान भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है" । द हिंदू बिजनेस लाइन । 24 सितंबर 2019 को मूल से संग्रहीत ।
26. योजना के राज्य सदस्य का कहना है, "केरल सरकार आयुष्मान भारत पर प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुई है" । बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया । पीटीआई. 9 जून 2019. 14 जून 2019 को मूल से संग्रहीत ।
27. कृष्णकुमार, आर. (12 अप्रैल 2019)। "केरल में एक बेहतर विकल्प" । अग्रिम पंक्ति । 30 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत । 15 फरवरी 2021 को लिया गया ।
28. खन्ना, रोहित (8 जून 2019)। "अगर पश्चिम बंगाल इस योजना में फिर से शामिल होता है तो आयुष्मान भारत का लक्ष्य 3 करोड़ लाभार्थियों का है" । द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया । 13 जनवरी 2020 को मूल से संग्रहीत ।

29. मेनन, अमरनाथ के. (9 सितंबर 2019)। "तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत को खारिज कर दिया" । इंडिया टुडे । 21 दिसंबर 2020 को मूल से संग्रहीत ।
30. "दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा: हर्ष वर्धन" । द इकोनॉमिक टाइम्स । पीटीआई.10 दिसंबर 2019. 15 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत ।
31. "आप सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करेगी: सिसोदिया" । द इकोनॉमिक टाइम्स । पीटीआई. 23 मार्च 2020. 12 जुलाई 2020 को मूल से संग्रहीत ।
32. टांडी, देव नारायण (31 मई 2020)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात 2.0' के 12वें एपिसोड को संबोधित किया " . narendermodi.in । 14 अप्रैल 2021 को मूल से संग्रहीत ।
33. कुमार, राजीव (20 मई 2020)। "आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई ने नया मील का पत्थर पार किया! व्हाट्सएप चैटबॉट, उत्सव के लिए विशेष ई-कार्ड की योजना बनाई गई" । द फाइनेंशियल एक्सप्रेस । 22 मई 2020 को मूल से संग्रहीत ।
34. "आयुष्मान भारत: अस्पतालों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा नया प्रयास" । इंडियन एक्सप्रेस । 26 नवंबर 2018 । 6 दिसंबर 2018 को लिया गया .
35. शर्मा, योगिमा सेठ (13 नवंबर 2019)। "लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईसी ने पीएमजेएवाई के साथ साझेदारी की" । द इकोनॉमिक टाइम्स । 20 अप्रैल 2021 को मूल से संग्रहीत ।
36. शर्मा, योगिमा (23 जून 2020)। "ईएसआईसी लाभार्थियों को जल्द ही आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल की सुविधाएं मिलेंगी" । द इकोनॉमिक टाइम्स ।
37. हुडा, शैलेन्द्र कुमार (26 नवंबर 2018)। "अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के साथ, क्या आयुष्मान भारत वास्तव में काम कर सकता है?" . तार। 27 नवंबर 2018 को मूल सेसंग्रहीत
38. निरूला, एसआर; नाइक, एम; गुप्ता, एसआर (जून 2019)। "एनएचएस बनाम मोदीकेयर: भारतीय हेल्थकेयर v2.0। क्या हम उस स्वस्थ भारत का निर्माण करने के लिए तैयार हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं?" . जर्नल ऑफ़ फ़ैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर । 8 (6): 1835-1837. डीओआई : 10.4103/jfmpc.jfmpc_309_19 । पीएमसी 6618227 । पीएमआईडी 31334141 .
39. "आयुष्मान भारत: अस्पताल सार्वजनिक धन को हड़पने के लिए विचित्र तरीकों का उपयोग करते हैं" । द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया । 15 अगस्त 2019 । 18 अगस्त 2019 को लिया गया ।
40. "आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं के लिए अस्पतालों को दंडित किया गया" । हिंदू बिजनेस लाइन25 जून 2019 । 18 अगस्त 2019 को लिया गया ।
41. "आयुष्मान भारत - PMJAY एक साथ: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के करीब एक कदम" । ओआरएफ. 24 सितंबर 2019.